आज का दिन 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

आकलन : भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी का इंजन बनी युवा आबादी

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान ब्यूरो

कोरोना महामारी और लॉकडाउन से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को फिर से दौड़ाने का काम युवा वर्ग (मिलेनियल्स) कर रहा है।

बीते दो महीने में गाड़ी, घर, इलेक्ट्रॉनिक समेत एफएमसीजी उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ाने में युवा आबादी की अहम भूमिका सामने आई है। बाजार के जानकारों का कहना है कि कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) ने पेशेवर युवाओं की जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन किया है।

युवा वर्ग इस बदलाव के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए घर, गाड़ी समेत तमाम जरूरी उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। इसका फायदा भारतीय बाजार को मिल रहा है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने घर को ही ऑफिस बन दिया है। इससे घरों की मांग तेजी से बढ़ी है। जुलाई-सितंबर तिमाही में घरों की बिक्री में बड़ा उछाल आया है। सामाजिक दूरी ने निजी वाहनों को बिक्री बढ़ाने का काम किया है।

18 फीसदी देश में युवा आबादी, इनमें पुरुष और महिला शामिल

25 करोड़ से अधिक आबादी देश में युवाओं कामगारों की यूएनडीपी के अनुसार

25 से 35 साल उम्र के खरीदार सबसे अधिक

पहले के मुकाबले युवा वर्ग ज्यादा गाड़ियां खरीदने पर फोकस कर रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी ने हिन्दुस्तान को बताया कि पहले गाड़ी खरीदने वालों में औसत उम्र 35 साल के ऊपर की होती थी लेकिन अब 25 से 35 साल के लोग ज्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद कोरोना के पहले के मुकाबले दो गुनी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज का युवा वर्ग ज्यादा लग्जरी गाड़ी खरीदने के चक्कर में नहीं है उसे उसकी जरूरत के मुताबिक अच्छी और एंट्री सेगमेंट की गाड़ी ज्यादा पसंद आ रही है। कोरोना महामारी के दौरान पैदा हुए हालात में अब सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किनारा करने के विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में खुद की गाड़ी ही सुरक्षित विकप्ल बचता है। गाड़ियों की मांग बढ़ने के प्रमाण सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) के ताजे आंकड़ों के अनुसार से भी मिला है। जुलाई-सितंबर 2020 की तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री 17.02 प्रतिशत बढ़कर 7,26,232 इकाई रही।

सूचना प्रौद्योगिकी पेशवरों ने बढ़ाई घरों की बिक्री

अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव ने हिन्दुस्तान को बताया कि कोरोना और लॉकडाउन ने घर को ही ऑफिस के रूप में बदल दिया है। वहीं, कई आईटी कंपनियों ने अगले साल तक के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। यह घर की बिक्री बढ़ाने का काम किया है। घरों की मांग सबसे अधिक युवा आईटी पेशवरों की ओर से बढ़ी है। उन्होंने प्रॉपटाइगर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अप्रैल-जून की तिमाही की तुलना में जुलाई-सितंबर की तिमाही में घरों की बिक्री 85 फीसदी बढ़ी है। त्योहारी सीजन में और सुधार की उम्मीद है।

नवरात्र से लौटेगी कारोबार में और तेजी

परिधान बाजार व्यापारियों को नवरात्र से कामकाज पटरी पर लौटने की आस है। कारोबारियों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण कपड़े से लेकर जूते-चप्पल की मांग खत्म हो गई थी लेकिन एक बार फिर से अनलॉक-5 के बाद मांग में तेजी आएगी। इस दफा बाजार में रौनक लाने में युवाओं की अहम भूमिका होगी क्योंकि पिछले सात महीने से उन्होंने बिल्कुल खरीदारी नहीं की है। ऐसे में दबी मांग से बाजार को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। कंपनियों की ओर से दी जा रही छूट का फायदा भी उपभोक्ता को मिलेगा।

बिजनेस आपतक

आईबीए के अध्यक्ष बने राजकिरण राय

नई दिल्ली। भारतीय बैंक संघ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राजकिरण राय को आईबीए का चेयरमैन चुना है।

डीसीएचएफसी ने गृह ऋण सस्ता किया

नई दिल्ली। दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड (डीसीएचएफसी) ने गृह ऋण पर ब्याज दरों को घटा दिया है। गृह ऋण पर ब्याज दरों को 8.25 प्रतिशत से घटाकर 7.45 प्रतिशत और 6.95 प्रतिशत कर दिया है।

एचसीएल नौ हजार भर्तियां करेगी

नई दिल्ली। एचसीएल का शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 18.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3,142 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में नौ हजार नये लोगों को काम पर रखने वाली है।

सोने की कीमत में 324 रुपये की तेजी

नई दिल्ली। सोने की कीमतों में पिछले तीन सत्रों से चली आ रही गिरावट थम गई। सोना 324 रुपये की तेजी के साथ 51,704 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी भी 1,598 रुपये बढ़कर 62,972 रुपये प्रति किलो रही।

इरडा ने बीमा कंपनियों को एमएसएमई कर्मियों के लिए बीमा पॉलिसी लाने को कहा

छोटे कामगारों को मिलेगा बीमा

तैयारी

नई दिल्ली | एजेंसी

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेयरमैन सुभाष खुंटिया ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वह सूक्ष्म, छोटे एवं मझौले उद्योग (एमएसएमई) के कामगारों के लिए भी बीमा उत्पाद पेश करें। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के साथ मिलकर कंपनियां इसके लिए सस्ती बीमा पॉलिसी पेश कर सकती हैं। खुंटिया ने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के स्वास्थ्य बीमा सम्मेलन में कहा, मैं बीमा कंपनियों से बीमारी केंद्रित और उत्पाद बनाने का आग्रह करूंगा।

खुंटिया ने कहा कि एक कंपनी यदि अपने कर्मचारी को 10 हजार रुपये प्रति माह वेतन देती है तो इसका मतलब है कि वह सालाना 1.20 लाख रुपये खर्च करती है। ऐसे में वह पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए पांच हजार रुपये प्रति कर्मचारी और खर्च कर सकती है। इरडा के अनुसार, कंपनियां आसानी से कामगारों के प्रीमियम का बोझ उठा सकती हैं। खुंटिया ने कहा कि एमएसएमई कामगारों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने को लेकर यह बहुत बड़ा कदम हो सकता है और कोरोना एवं लॉकडाउन ने हमें इसका महत्व समझा दिया है।

खुंटिया ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से मधुमेह, किडनी की समस्या जैसी बीमारियों पर केंद्रित उत्पाद लाने को कहा। इरडा के चेयरमैन ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लोगों की जरूरतों के अनुसार नए-नए उत्पाद लाने चाहिए। खुंटिया ने कहा, मैं बीमा कंपनियों से बीमारी केंद्रित और उत्पाद बनाने का आग्रह करूंगा। जैसे मधुमेह, हृदय या किडनी संबंधित बीमारियों के लिए अलग से उत्पाद बनाए जा सकते हैं। खुंटिया ने यह भी कहा कि अभी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य बीमा 40 से 50 साल के आयु वर्ग के लोग ले रहे हैं।

ओपीडी-सालाना स्वास्थ्य जांच का कवर दें

इरडा के चेयरमैन ने कहा कि बीमा कंपनियों को बीमा कवर का दायरा ओपीडी और सालाना स्वास्थ्य जांच तक बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी केंद्रित उत्पादों के तहत बीमा कंपनियां विशेषज्ञ डॉक्टरों को जोड़ सकती हैं ताकि पॉलिसीधारकों को विभिन्न बीमारियों से बचने के उपायों के बारे में अवगत कराया जा सके। खुंटिया ने सुझाव दिया कि बीमा कंपनियां अपने उत्पादों में टीके आदि को शामिल कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने पॉलिसीधारकों को रोग निरोधी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देने को कहा।

05 लाख रुपये के बीमा पर कंपनियों को पांच हजार रुपये खर्च करने होंगे

4.7 फीसदी जीडीपी के अनुपात में देश में बीमा उपलब्धता

13.4 फीसदी की रफ्तार से बढ़ा स्वास्थ्य बीमा कारोबार सितंबर तिमाही में

छोटे शहरों में पहुंच बढ़ाएं

इरडा के चेयरमैन ने बीमा कंपनियों को दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में भी बीमा पहुंच बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों को युवा आबादी को आकर्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को आकर्षित करने के लिए ऐसे जांच या इलाज को बीमा उत्पाद में शामिल करने का सुझाव दिया जिसके लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होने की जरूरत नहीं है।

नई बीमा कंपनियों ने दिए आवेदन

बीमा नियामक इरडा के पास 176 कंपनियों ने बीमा कारोबार शुरू करने के लिए आवेदन दिए हैं। इनमें से ज्यादातर स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में उतरना चाहती हैं। इसके मद्देनजर बीमा नियामक कारोबार शुरू करने की शर्तों में राहत देने की तैयारी है। इरडा ने सुझाव दिया है कि बीमा कारोबार शुरू करने के लिए मौजूदा 100 करोड़ रुपये की पूंजी की शर्त को घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया जाए।

वेतन वृद्धि रिपोर्ट को किया खारिज

नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को मीडिया में आई उन रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) की नई श्रृंखला आने से सरकारी और औद्योगिक कामगारों के वेतन में बढ़ोतरी होगी।

सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग मुख्य रूप से सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और बीमा कंपनियों समेत संगठित क्षेत्र में काम करने वालों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मापने में किया जाता है।

बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को 2021-22 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह प्रक्रिया ऐसे समय शुरू हुई है जब कोविड-19 संकट से प्रभावित आर्थिक वृद्धि को गति देने की जरूरत है।

वित्त मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार 2020-21 के संशोधित अनुमान (आरई) और 2021-22 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिये करीब एक महीने चलने वाली प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई। बैठकें 12 नवंबर तक चलेंगी।

जीएसटी मुआवजे पर वित्त मंत्री की राज्यों को चिट्ठी

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

कवायद

- राज्यों के लिए उधार सुविधा जल्द लागू करने जा रहा केन्द्र
- राज्य जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे उसका उन्हें अहसास है

राज्यों के बकाए जीएसटी मुआवजे के मुद्दे को लेकर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। वित्तमंत्री ने कहा है हालांकि केंद्र सरकार भी फिलहाल भारी वित्तीय दबाव के दौर से गुजर रही है लेकिन खास व्यवस्था के जरिए राज्यों के लिए उधार की सुविधा जल्द लागू करने जा रही है। ताकि मुश्किल दौर में राज्यों को भी तत्काल आर्थिक मदद मिल सके।

सूत्रों ने हिन्दुस्तान को बताया है कि इसी के बारे में जानकारी देते हुए वित्तमंत्री ने राज्यों को लिखा है। वित्तमंत्री सीतारमण ने ये भी कहा है कि कोरोना महामारी के चलते राजस्व पर बुरा असर हुआ है। ऐसे में राज्य भी जिन वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उसका उन्हें अहसास है।

वित्तमंत्री ने राज्यों को ये भी लिखा है कि कई राज्यों के सुझावों के बाद अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ का उधार लेगी। इसके बाद लोन के तौर पर राज्यों को यह रकम देगी।

अटल बीमित योजना की रफ्तार बढ़ेगी

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

देश में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की सुस्त रफ्तार को देखते हुए इसके लिए खास अभियान लॉन्च करने जा रही है। इस योजना के जरिए नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को 50 फीसदी सैलरी दिए जाने का प्रावधान है।

हिन्दुस्तान को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक इस स्कीम का फायदा लेने वालों का आंकड़ा एक लाख भी नहीं पहुंचा है। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक संबंधित विभाग फिलहाल अब तक आए क्लेम को निपटाने में जुटे हुए हैं साथ ही आने वाले दिनों में लोगों के बीच इस स्कीम को लेकर जागरुकता फैलाने का भी काम तेजी से किया जाना है। इसके लिए सोशल मीडिया समेत प्रमुख माध्यमों का इस्तेमाल किया जाना है।

सरकार का मानना है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानि ईएसआईसी के तहत चलाई गई इस योजना के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा दिया जा सकता है। फिलहाल इसके फंड के तहत करीब 40 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसका इस्तेमाल नौकरी गंवा चुके लोगों के लिए किया जा सकता है।

कैसे मिलेगा फायदा

इस अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ईएसआईसी में नामांकित व्यक्ति की नौकरी अगर कोरोना संकट के चलते गई है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ऐसे लोगों को तीन महीने तक उनकी सैलरी की 50 फीसदी राशि प्रदान की जाएगी। यह मदद उन लोगों को मिलेगी जिनकी नौकरी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच चली गई होगी। पहले इस स्कीम के तहत मिलने वाली रकम 50 के बजाए 25 फीसदी हुआ करती थी लेकिन कोरोना काल में सरकार ने इसमें इजाफा किया है। इसके लिए यह भी शर्त है कि क्लेम करने वाले व्यक्ति का इंश्योरेंस कम से कम दो साल तक रहा हो।

सितंबर तिमाही में वाहन बिक्री 17 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली | एजेंसी

खरीदारों की धारणा में सुधार तथा त्योहारी मौसम की बढ़ी मांग को पूरा करने की कंपनियों की तैयारी के कारण चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 17 प्रतिशत बढ़ गई। वाहन विनिर्माता कंपनियों के संगठन सिआम ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सिआम) के ताजे आंकड़ों के अनुसार, जुलाई-सितंबर 2020 की तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 17.02 प्रतिशत बढ़कर 7,26,232 इकाई रही। साल भर पहले यह 6,20,620 इकाई रही थी। सितंबर तिमाही के दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री इस वित्त वर्ष में 46,90,565 इकाई रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 46,82,571 इकाई थी। हालांकि, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 20.13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।

खुदरा वाहन बिक्री में तेजी ने जगाई उम्मीद

सितंबर महीने में देश में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 26.45 प्रतिशत बढ़कर 2,72,027 इकाइयों पर पहुंच गयी। साल भर पहले यानी सितंबर 2019 में 2,15,124 खुदरा वाहनों की बिक्री हुई थी। इस दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री 11.64 प्रतिशत बढ़कर 18,49,546 इकाइयों पर पहुंच गई।

तिमाही में वाहन उद्योग के उबरने के संकेत

सिआम के अध्यक्ष केनिचि आयुकावा ने कहा, दूसरी तिमाही में कुछ श्रेणियों में उबरने के संकेत मिल रहे हैं। यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों में सकारात्मक रुख है। वाणिज्यिक और तिपहिया वाहनों जैसे अधिकांश उद्योग खंडों में बिक्री पांच-छह साल पहले की समान तिमाही के स्तर पर रही है। उद्योग ते त्योहारों में बिक्री बढ़ने की आस है।

लोन गारंटर बनने से बढ़ सकती है मुसीबत

नई दिल्ली | रेणु यादव

कोरोना महामारी ने अधिकांश लोगों की वित्तीय स्थिति को कमजोर किया है। इसके चलते बैंक से लोन लेने वालों की संख्या आने वाले समय में बढ़ सकती है। ऐसे में अगर आपका कोई रिश्तेदार लोन लेना चाह रहा है और आपको उसका गारंटर बनाना चाहता है तो संभलकर निर्णय लें।

गारंटर का मतलब सिर्फ एक कागज पर दस्तखत करना नहीं होता है। इससे आपकी लोन लेने की व्यक्तिगत क्षमता कम हो जाती है।

गारंटर बनने से पहले ये जानें :
अगर आप गारंटर बन रहें तो यह पहले पता करें कि बैंक आपको किस तरह का गारंटर बना रहा है। बैंक दो तरह के गारंटर बनाते हैं, गैर-वित्तीय गारंटर और वित्तीय गारंटर। एक गैर-वित्तीय गारंटर लोन चुकाने में देरी होने पर बैंक और कर्जदाता को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। दूसरी तरफ, एक वित्तीय गारंटर को, उधारकर्ता द्वारा लोन नहीं चुकाने की स्थिति में उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है।

घट जाएगी आपकी ऋण लेने की योग्यता

लोन गारंटर का मतलब है कि बैंक को कर्ज लेने वाले पर पूरा भरोसा नहीं है कि वह कर्ज लौटा पाएगा। बैंक अपने लोन की सुरक्षित करने के लिए गारंटर मांगता है। ये गारंटी अचल संपत्ति के रूप में या किसी व्यक्ति के रूप में हो सकता है। ऐसे में गारंटर बनने से पड़ताल करें।

खराब होगा क्रेडिट स्कोर

अगर आप किसी लोन का वित्तीय गारंटर हैं और लोन लेने वाले व्यक्ति ने कर्ज नहीं चुकाया है तो आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। बैंक के एक अधिकारी के मुताबिक, सिबिल केवल कर्जदारों की सूचनाएं ही नहीं जुटाता है बल्कि गारंटी देने वालों का रिकॉर्ड भी रखता है।

डिफॉल्ट होने पर क्या है रास्ता

अगर कर्ज लेने वाला व्यक्ति नियमित रूप से ईएमआई का भुगतान नहीं कर रहा है तो सबसे अच्छा तरीका पारिवारिक और सामाजिक दबाव डालना है। यदि वह नहीं मानता है तो उससे कानूनी रूप से निपट सकते हैं। अगर आप पहले ही गारंटर हैं तो कर्ज लेने वाले व्यक्ति और कर्ज देने वाले बैंक से भी संपर्क में रहें। इसके अलावा अपना क्रेडिट स्कोर भी नियमित रूप से चेक करें।

mint

सेंसेक्स में 254 अंक की तेजी

मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को लिवाली बढ़ने से तेजी लौट आई जिससे बीएसई सेंसेक्स 254.57 अंक चढ़कर 39,982.98 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 82 अंक बढ़कर 11,762 अंक पर बंद हुआ।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER TRANSMISSION LINE
MAINTT. DIVISION-VIII, AMBEDKAR CHOWK, JAMMU
Email:-xentlcd01@gmail.com, Fax No. :- 0191-2451732

NOTICE INVITING TENDER

e-NIT No.:- TLMD-VIII/J/14 of 2020-21 **Dated:- 12.10.2020**

Executive Engineer TLMD-VIII, Jammu, for and on behalf of Managing Director JKPTCL, Jammu, wishes to receive online e-bids for **Design Engineering, Survey, Soil Testing/Investigation, Fabrication of Lattice Type Tower Structures, Galvanization, Supply of Structures, Laying of Foundations, Protection Works, Erection of three no. towers (one no. B+3 type and two nos. D+0 type towers), Laying & Stringing of ACSR 'PANTHER' Conductor, Dismantling & de stringing of 3 Nos. tower, Testing and Commissioning including transportation, insurance, handling, storage of material etc at site for realignment of 132 KV D/C Gladni-Nagrota Transmission Line near IMPA Jammu, J&K**, in all respects as specified in technical specification. Submission of e-bid against this standard Bidding Document (SBD) shall be deemed to have been done after careful study and examination of the procedure, terms and conditions of the standard bidding document with full understanding of its implications. The tender document is available at website **http://jktenders.gov.in**. Interested bidders may view/download the e-bid document, submit their e-bid online upto date and time mentioned in the table below:-

Scope of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Tender Documents	Last Date of e-bids submission online	Class of Contractor
Design, Engineering, Survey, Soil Testing/Investigation, Fabrication of Lattice Type Tower Structures, Galvanization, Supply of Structures, Laying of Foundations, Protection Works, Erection of three no. towers (one no. B+3 type and two nos. D+0 type towers), Laying & Stringing of ACSR 'PANTHER' Conductor, Dismantling & de stringing of 3 Nos. tower, Testing and Commissioning including transportation, insurance, handling, storage of material etc at site for complete job of realignment of **132 KV D/C Gladni-Nagrota Transmission Line near IMPA Jammu, J&K**.	Rs. 103.39 (One hundred three Lacs And thirty nine thousand rupees only)	Rs. 2.06 lacs (two lacs and six thousand)	Rs. 5000 (Rupees Five Thousand Only) (non-refundable)	02.11.2020 upto 1600 Hrs	"A" Class

Other Details:

1.	**Date & Time of downloading of Standard Bidding Document**	The Standard Bidding Document can be downloaded over **http:/jktenders.gov.in** from date 13.10.2020 (1000 Hrs. onwards)
2.	**Pre-bid meeting**	Shall be conducted on 19.10.2020 at 1300 Hrs. in the Office of the Executive Engineer TLMD-VIII Jammu, J&K.
3.	**e-Bid submission (starts) date & time (submission of e-tender fee, EMD and other supporting documents in PDF/XLS format)**	13.10.2020 from 1000 Hrs.
4.	**e-Bid submission (end) date & time**	02.11.2020 up to 1600 Hrs.

No.: TLMD-VIII/J/795-98
Dated: 12.10.2020

Sd/-
Executive Engineer
Trans. Line Maintenance Division-VIII
JKPTCL, Jammu

DIP-J-2041-P-20

HCL TECHNOLOGIES LIMITED
Corporate Identity Number : L74140DL1991PLC046369
Registered Office : 806, Siddharth, 96 Nehru Place, New Delhi, 110 019
Corporate Office : Plot No. 3A, Sector 126, Noida 201 304, U.P., India
Website: www.hcltech.com; Telefax: +91 11 26436336

Extract of Consolidated Financial Results of HCL Technologies Limited as per Ind AS: (₹ in crores)

Particulars	Three months ended 30 September 2020 (Unaudited)	Six months ended 30 September 2020 (Unaudited)	Three months ended 30 September 2019 (Unaudited)
Total income from operations	18,594	36,436	17,527
Net profit for the period before tax, exceptional and/or extraordinary items	4,145	8,007	3,478
Net profit for the period before tax	4,145	8,007	3,478
Net profit for the period after tax	3,146	6,081	2,711
Net profit for the period after tax and non-controlling interest	3,143	6,074	2,711
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and non-controlling interest and other comprehensive income after tax)	3,201	6,436	2,792
Equity share capital (par value ₹ 2 each)	543	543	271
Other equity as at 31 March 2020			50,724
Earnings per equity share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations) (₹)			
Basic (in ₹)	11.58	22.38	9.99
Diluted (in ₹)	11.58	22.38	9.99

Extract of Standalone Financial Results of HCL Technologies Limited as per Ind AS: (₹ in crores)

Particulars	Three months ended 30 September 2020 (Unaudited)	Six months ended 30 September 2020 (Unaudited)	Three months ended 30 September 2019 (Unaudited) Refer note 5
Total income from operations	8,658	17,020	8,147
Net profit for the period before tax, exceptional and/or extraordinary items	3,234	6,309	2,813
Net profit for the period before tax	3,234	6,309	2,813
Net profit for the period after tax	2,530	4,890	2,245
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	2,748	5,260	2,192
Equity share capital (par value ₹ 2 each)	543	543	271
Other equity as at 31 March 2020			37,003
Earnings per equity share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations) (₹)			
Basic (in ₹)	9.32	18.02	8.28
Diluted (in ₹)	9.32	18.02	8.27

Notes:

1. The consolidated and the standalone financial results for the quarter and six months ended 30 September 2020 were reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 16 October 2020. The statutory auditors have issued review report with unmodified opinion on these results.
2. The Board of Directors at its meeting held on 7 May 2020 has recommended a final dividend of ₹ 2/- per share. The same was approved by shareholders in the Annual General Meeting of the Company held on 29 September 2020.
3. The Board of Directors at its meeting held on 16 October 2020 has declared an interim dividend of ₹ 4/- per share.
4. Financial results for all the periods presented have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended from time to time) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
5. The Hon'ble National Company Law Tribunal of New Delhi and Bengaluru have approved the Scheme of Amalgamation providing for the merger of four direct /step-down wholly-owned subsidiaries engaged in providing IT and IT related services viz. HCL Eagle Limited, HCL Comnet Limited, HCL Technologies Solutions Limited and Concept2Silicon Systems Private Limited (the "Transferor companies") with and into HCL Technologies Limited (the "Transferee company") with effect from 01 April 2019, the appointed date. The scheme has become effective on 13 July 2020 on filling of the certified true copy of the Orders of the Delhi and the Bengaluru NCLT with the Registrar of Companies on 13 March 2020 and 13 July 2020 respectively.
   Since the Transferor Companies are the wholly-owned subsidiaries of the Transferee Company, there will be no issue and allotment of shares as consideration. The difference between the amounts recorded as investments of the Company (Transferee Company) and the amount of share capital of the aforesaid amalgamating subsidiaries (Transferor Companies) has been adjusted in the Common Control Transaction Capital Reserve. The comparative results have been restated for all period presented as per guidance under Appendix C of Ind AS 103 "Business Combinations".
   The impact of the scheme is not material on the standalone financial results of the company.
6. In view of pandemic relating to COVID-19, the group has considered and taken into account internal and external information on current estimates in assessing the recoverability of receivables, unbilled receivables, goodwill, intangible assets, other financial assets, impact on revenues and costs, impact on leases and effectiveness of its hedging relationships. However, the actual impact of COVID-19 on the Group's financial statements may differ from that estimated and the Group will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.
7. On 21 September 2020, the Group through a wholly owned subsidiary, has announced its intent to acquire 100% stake in DWS Limited, a leading Australian IT, business and management consulting group for ₹ 831 crores (AUD 158.20 million) payable in cash. DWS Shareholders will also get a dividend of ₹ 21 crores which was declared by the DWS in its recent announcement of annual corporate earnings for year ending 30 June 2020. The transaction is expected to close by December 2020, subject to regulatory approvals.
8. The Indian Parliament has approved the Code on Social Security, 2020 which would impact the contributions by the Group towards Provident Fund and Gratuity. The effective date from which the changes are applicable is yet to be notified and the rules are yet to be framed. The Group will carry out an evaluation of the impact and record the same in the financial statements in the period in which the Code becomes effective and the related rules are published.
9. The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the Stock Exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com, and on the Company's website, www.hcltech.com.

By the order of the Board of Directors
for HCL Technologies Limited

Shiv Nadar
Chief Strategy Officer

C. Vijayakumar
President and Chief Executive Officer

Prateek Aggarwal
Chief Financial Officer

Noida (UP), India
16 October 2020

HCL